एचडीएफसी लाइफ का शुद्ध लाभ 15 फीसद बढ़ा

नई दिल्ली : एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने शुद्ध लाभ में खासी वृद्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 2018-19 में कंपनी का शुद्ध लाभ 15 फीसद बढ़कर 1,277 करोड़ रुपये हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2017-18 में यह 1,109 करोड़ रुपये था। कंपनी ने नए कारोबार के प्रीमियम में पिछले वित्त वर्ष में 32 फीसद वृद्धि दर्ज की है। एचडीएफसी लाइफ की प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी विभा पडलकर ने कहा कि कंपनी ने उद्योग के स्तर के अनुरूप वृद्धि और मुनाफे के लिहाज से नेतृत्व की स्थिति बरकरार रखी है। (वि)

सरकार विकास को गति देने के लिए जिला आधारित विकास मॉडल पर काम कर रही है। इसके लिए देश के छह जिलों को चुना गया है।

– सुरेश प्रभु
वाणिज्य व उद्योग मंत्री

तेजी ▶ अप्रैल में 1.10 लाख करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच सकती है कलेक्शन की राशि

इस माह रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह की आस

अप्रैल में कंपोजीशन स्कीम के कारोबारी भी भरेंगे मार्च तिमाही का टैक्स

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अनुपालन में सुधार के लिए सरकार की कोशिशों का असर अब दिखने लगा है। अप्रैल माह में जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) के सूत्रों का कहना है कि अप्रैल में जीएसटी में पंजीकृत नियमित कारोबारियों के साथ-साथ कंपोजीशन स्कीम के डीलरों ने भी जनवरी-मार्च, 2019 के लिए रिटर्न दाखिल किया है, जिससे इस माह जीएसटी संग्रह में उछाल आने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि अप्रैल में जीएसटी संग्रह 1.10 लाख करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच सकता है। सरकार जीएसटी संग्रह के आंकड़े पहली मई को जारी करेगी।

कंपोजीशन स्कीम के तहत आने वाले डीलर तीन माह में एक बार रिटर्न दाखिल करते हैं। फिलहाल जीएसटी में 1.31 करोड़ कारोबारी पंजीकृत हैं जिनमें से 17.74 लाख ने कंपोजीशन स्कीम ले रखी है। हाल के महीनों में जीएसटी अनुपालन में सुधार होने से जीएसटी संग्रह बढ़ा है। केंद्र और राज्य सरकारों ने अपने-अपने स्तर पर जीएसटी अनुपालन में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। जीएसटी चोरी रोकने के लिए ई-वे बिल की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा रिटर्न फाइलिंग में जटिलताओं को दूर करने का काम भी किया गया है। इस साल मार्च में जीएसटी संग्रह 1.06 लाख करोड़ रुपये रहा था जो जीएसटी लागू होने के बाद का सर्वाधिक मासिक संग्रह है। इसी का नतीजा था कि सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए संशोधित अनुमानों से अधिक जीएसटी संग्रह किया। मार्च में 75.95 लाख रिटर्न दाखिल हुए थे जो किसी एक महीने में दाखिल रिटर्न की सर्वाधिक संख्या है।

सूत्रों ने कहा कि अनुपालन में सुधार की वजह से ही बीते वित्त वर्ष में औसत मासिक जीएसटी संग्रह 98,114 करोड़ रुपये रहा जो वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में 9.2 फीसद अधिक है। गौरतलब है कि हाल ही में सरकार ने जीएसटी दरों को ज्यादा तर्कसंगत बनाया था।

बीते वित्त वर्ष में सरकार को जीएसटी से मिली इतनी राशि

माह	संग्रह (करोड़ रुपये)
अप्रैल	1,03000
मई	94,106
जून	95,610
जुलाई	96,483
अगस्त	93,960
सितंबर	94,442
अक्टूबर	1,00,710
नवंबर	97,637
दिसंबर	94,725
जनवरी	1,02,000
फरवरी	97,247
मार्च	1,06,577

ट्रंप के ट्वीट के बाद कच्चे तेल में गिरावट

नई दिल्ली, आइएएनएस : कच्चे तेल के ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट में शनिवार को तीन फीसद तक की गिरावट दर्ज की गई। इस नरमी के साथ कच्चा तेल गिरकर 71 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। इस सप्ताह ब्रेंट 75 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर चला गया था, जो इस साल का उच्च स्तर था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक ट्वीट कर तेल उत्पादक व निर्यातक देशों के समूह ओपेक को उत्पादन बढ़ाने को कहा था, ताकि कच्चे तेल की बढ़ती कीमत को रोका जा सके। बाद में उन्होंने यह भी ट्वीट किया कि मैंने सऊदी अरब और अन्य देशों से तेल उत्पादन बढ़ाने को कहा है। सब इससे सहमत हैं।

गौरतलब है कि अमेरिका ने किसी भी देश द्वारा ईरान से कच्चा तेल खरीदने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। परमाणु अप्रसार पर ईरान से बातचीत बेनतीजा रहने के बाद पिछले वर्ष नवंबर में अमेरिका ने ईरान से किसी भी देश के तेल सौदे पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि उसने भारत समेत आठ देशों को छह महीने तक तेल खरीदते रहने की छूट दी थी और कहा था कि ये देश तब तक ईरान से तेल खरीद को शून्य पर ले आएं। यह अवधि मई के पहले सप्ताह में खत्म हो जाएगी। अमेरिका ने छूट की यह अवधि बढ़ाने से इन्कार कर दिया।

डाटा लोकलाइजेशन के जोखिम बहुत हैं : मार्क जुकरबर्ग

फेसबुक प्रमुख ने कहा, नागरिकों पर ज्यादा नियंत्रण रखने वाले देश भी करने लगेंगे मांग तो बढ़ेगी दिक्कत

नई दिल्ली, आइएएनएस : सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक और सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि डाटा लोकलाइजेशन संबंधी भारत की मांग वाजिब है। लेकिन किसी एक देश के लिए इसकी अनुमति देने से अन्य देश भी इसकी मांग में उठ खड़े होंगे। जुकरबर्ग ने कहा कि ऐसी स्थिति में किसी तानाशाह या जनता पर ज्यादा नियंत्रण रखने वाले देश ने डाटा लोकलाइजेशन की मांग की, तो वह अपने नागरिकों की सूचनाओं का गलत इस्तेमाल कर सकता है।

इतिहासकार और लेखक युवल नोह हरारी से वार्तालाप में जुकरबर्ग का कहना था कि डाटा लोकलाइजेशन यानी स्थानीयकरण की मांग का उद्देश्य सबसे ज्यादा मायने रखता है। उन्होंने कहा, 'उद्देश्य निश्चित तौर पर मायने रखता है। और मैं मानता हूं कि हममें से कोई भी भारत को एक नियंत्रणकारी देश के रूप में नहीं देखना चाहेगा।'

जुकरबर्ग का कहना था कि भारत अपने नागरिकों के मूल्यों के प्रति खुला रवैया रखता है। लेकिन ऐसे बहुत से देश हैं जिनका अपने नागरिकों के प्रति रवैया उतना खुला नहीं है। अगर उन्होंने नागरिकों पर नजर रखने या उन्हें जेल भेजने के लिए उन सूचनाओं का इस्तेमाल किया, तो दिक्कत हो सकती है।

मामला क्या है

पिछले कुछ समय से भारत वीजा, मास्टरकार्ड और फेसबुक समेत उन सभी कंपनियों को अपने यूजर्स का डाटा भारत में ही संग्रहित करने को कह रहा है, जिनके सर्वर किसी अन्य देश में हैं। भारत का तर्क है कि डाटा किसी अन्य देश में संग्रहित होने की वजह से विशेष परिस्थितियों में किसी यूजर की सूचनाओं तक पहुंचने में कानूनी प्रक्रियाओं के चलते देरी होती है। कंपनियों का तर्क है कि हर देश के लिए स्थानीय स्तर पर डाटा संग्रहित करने के लिए उन्हें इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा निवेश करना होगा, जो कई कंपनियों के लिए मुश्किल है।

बुजुर्ग नागरिकों को साइबर ठगी से बचाने की जिम्मेदारी बैंकों को उठानी ही होगी

धीरेंद्र कुमार, सीईओ वैल्यू रिसर्च

बोनस

आपके पास एक फोन आता है जिसमें कहा जाता है कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, उसे चालू रखने के लिए आपके मोबाइल फोन पर भेजा गया ओटीपी बताएं। आप बता देते हैं और थोड़ी ही देर में पता चलता है कि आपके खाते पर कोई हाथ फेर गया है। दूसरी बार बहाने अकाउंट बंद होने के अलावा दर्जनों हो सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया लगभग यही होती है। इसका सबसे ज्यादा शिकार बुजुर्ग हो रहे हैं। लेकिन क्या ओटीपी-आधारित इस ठगी को रोकना इतना मुश्किल काम है? अगर आसान है तो बैंक ये कदम उठाते क्यों नहीं?

यूं तो मैं सामान्यतया निवेश से जुड़े विषयों के बारे में ही बात करता हूं। लेकिन इस बार मैं एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जो वित्तीय मुद्दों से बिल्कुल जुदा है। वह है बैंक अकाउंट की सुरक्षा का मुद्दा। वरिष्ठ नागरिकों के साथ डिजिटल ठगी के इतने किस्से अब आस-पास सुनाई देने लगे हैं कि उनकी गिनती करना असंभव है। अब तो जान-पहचान वालों में भी हर महीने कोई न कोई ऐसी घटना सुनने में आ ही जाती है कि किसी बुजुर्ग के मोबाइल फोन पर तीन-चार कॉल आए, उनसे मोबाइल फोन पर आया ओटीपी यानी 'वन टाइम पासवर्ड' मांगा गया, उन्होंने ओटीपी दे दी और फिर डिजिटल ठगों ने उनके अकाउंट पर हाथ फेर दिया।

इस पूरे खेल में डिजिटल ठगी के उस्ताद अक्सर अकाउंट से उन वस्तुओं का लेनदेन करते हैं, जो आसानी से बिक जाती हैं या जिन्हें जल्द से जल्द भुनाया जा सकता है। मसलन, वे किसी के अकाउंट से ज्वैलरी खरीद लेते हैं जिन्हें कहीं भी बेचना आसान है। चिंता की बात यह है कि ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए उचित कदम उठाने में बैंक लगातार विफल साबित हो रहे हैं।

यह साबित करने के तमाम सुबूत मौजूद हैं कि बुजुर्गों से मोबाइल फोन पर ओटीपी मांगकर ठगी करने का यह तरीका भारत में हो रहे डिजिटल अपराधों में सबसे प्रमुख है। इसके बावजूद इस बात के सुबूत नहीं मिलते कि विभिन्न बैंक या बैंकिंग नियामक (आरबीआइ) इसे रोकने के प्रति गंभीर हैं। बैंक इसे रोकने के बारे में बातें तो बहुत करते हैं। वे अपने ग्राहकों को लगातार यह संदेश भी भेजते रहते हैं कि किसी को ओटीपी न दें। बैंक कहते हैं कि अगर आपने ओटीपी दे दिया तो फिर सारी जिम्मेदारी आपकी है।

एक विचित्र बात यह भी है कि ओटीपी के बारे में तो हम इतनी बातें करते हैं। लेकिन किसी धोखाधड़ी में ओटीपी की प्रक्रिया तक पहुंचने से पहले क्या-क्या होता है, इसके बारे में न तो पर्याप्त सूचना उपलब्ध है और न इस बारे में विभिन्न बहस-मुबाहिसों में बात की जाती है। आखिर अपराधी को किसी का क्रेडिट या डेबिट कार्ड का नंबर और उसके पीछे छपा तीन अंकों का सीवीवी नंबर कहां से मिल जाता है?

मैं कई ऐसे मामले जानता हूं जिसमें इस तरह की ठगी के शिकार बुजुर्ग ने स्थानीय एटीएम को छोड़कर किसी भी अन्य जगह पर अपने कार्ड का कभी उपयोग नहीं किया। उन्हें पता ही नहीं कि ऑनलाइन लेनदेन कैसे किया जाता है, तो वे उपयोग करेंगे कहां। इसके बावजूद उनसे हजारों किलोमीटर दूर किसी राज्य में उनके कार्ड से ऑनलाइन लेनदेन हो गया। ऐसा होने की एकमात्र सूरत यह बनती है कि उनके कार्ड डिटेल बैंक से ही लीक हुए, क्योंकि उस कार्ड का एटीएम के अलावा कहीं और उपयोग का कोई इतिहास नहीं है। लेकिन बैंकों का पूरा फोकस ओटीपी पर रहता है। असल में इस तरह के अपराधों की गुत्थी सुलझाने और ऐसे अन्य संभावित अपराधों को रोकने के लिए हमें शुरुआत इसकी जड़ से ही करनी पड़ेगी। वह है - कार्ड के डाटा की चोरी होना।

इस बीच, पिछले दिनों हमने देखा कि देशभर में पुराने डेबिट कार्ड्स को चिप-आधारित कार्ड्स से बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन चिप-आधारित कार्ड से सिर्फ एक अपराध रुक सकता है - कार्ड की क्लोनिंग और फर्जी कार्ड बना लेना। कार्ड की क्लोनिंग में तकनीकी विशेषज्ञता और खास तरह के उपकरणों की जरूरत होती है। कुल मिलाकर नए चिप-आधारित कार्ड से किसी अन्य कंपनी (जो इस तरह के कार्ड का निर्माण करती है) की कमाई तो हो रही है। लेकिन बुजुर्ग पुरुषों-महिलाओं से मीठी-मीठी बातें कर उन्हें बहला-फुसलाकर ओटीपी मांगकर ठगी करने का धंधा कुटीर उद्योग की शक्ल ले चुका और फल-फूल रहा है।

इस तरह के अपराधों को रोकना मुश्किल नहीं है। कुछ सामान्य उपाय हैं जिन्हें अपनाकर दुनियाभर के कई देश इस तरह के अपराधों में उल्लेखनीय कमी ला चुके हैं।

पहला : बैंकों के आंतरिक डाटाबेस में कुछ 'ट्रेसर' कार्ड नंबर और उनसे जुड़े ग्राहकों के छद्म विवरण होने चाहिए। अगर इन कार्ड्स में कभी धोखाधड़ी से संबंधित कोई गतिविधि नजर आती है, तो समझ जाना चाहिए कि डाटा निश्चित तौर पर बैंक के अंदर से ही लीक हुआ है। डाटा की इस तरह की चोरी का सही वक्त पर पता लगाने के लिए बैंकों को नियमित अंतराल पर अपने छद्म डाटाबेस में कुछ नए ग्राहकों के नाम शामिल करने और कुछ के हटाते रहने चाहिए।

दूसरा : ओटीपी को किसी खास समय तक के लिए वैध करने के बदले उसे खास लेनदेन के लिए वैध करना चाहिए। मसलन, ओटीपी के लिए मोबाइल पर जो संदेश आता है, उसमें स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि अमुक दुकान पर अमुक राशि के लेनदेन के लिए ही यह ओटीपी है। इससे कार्ड धारक को पक्का पता चल जाएगा कि कार्ड का उपयोग कहां और किस मद में हो रहा है। बैंकों को भी इससे उस कार्ड के लेनदेन का पता लगाने में आसानी होगी।

तीन : ऑनलाइन गतिविधि किस स्थान से हो रही है, इसका उपयोग आजकल हर पेशेवर वेबसाइट कर रही हैं। अगर बैंक सच में ओटीपी-आधारित धोखाधड़ी को रोकने के प्रति गंभीर हैं, तो उन्हें ओटीपी वाले संदेश के साथ लेनदेन की जगह का भी नाम देना चाहिए। मसलन, 'यह ओटीपी 50,000 रुपये के लेनदेन के लिए एबीसीडी डॉट कॉम पर किसी विकास कुमार नामक ग्राहक के लिए आसनसोल नामक स्थान पर वैध है।'

चार : बुजुर्ग ग्राहकों के लिए बैंक एक तरीका यह भी अपना सकते हैं कि एक निश्चित रकम से बड़े लेनदेन के लिए दो ओटीपी या विभाजित ओटीपी भेजें। इनमें एक ओटीपी या उसका एक हिस्सा ग्राहक के मोबाइल फोन पर, जबकि दूसरा हिस्सा उसी परिवार के किसी युवा सदस्य के मोबाइल फोन पर जाए। इससे अपराधी की भी राह मुश्किल हो जाएगी।

इसके अलावा भी कई ऐसे तरीके हैं जिन्हें अपनाकर ओटीपी-आधारित धोखाधड़ी पर लगाम कसी जा सकती है। हालांकि इनमें से कोई भी तरीका पूरी तरह ठगी को पूरी तरह रोक नहीं सकता। लेकिन इतना जरूर है कि इन्हें अपनाने से वरिष्ठ नागरिकों के प्रति होने वाले ऐसे अपराधों में बड़ी कमी लाई जा सकती है और उन्हें धन की हानि और मानसिक अशांति से निजात मिल सकती है।

क्या भारतीय बैंक ये सब कदम उठाएंगे? यकीन मानिए, अगर उनमें इस तरह के कदम उठाने की इच्छा होती, तो वे कब का उठा चुके होते। इनमें से कोई भी कदम इतना अनोखा या मुश्किल नहीं, क्योंकि दुनियाभर में कहीं न कहीं इनमें से सभी कदमों का उपयोग किया जा रहा है। इसलिए गेंद अब बैंकिंग नियामक यानी आरबीआइ के पाले में है। अगर वह देश के बुजुर्गों को वित्तीय अपराधों से सुरक्षित रखना चाहता है, तो उसे बैंकों को कम बातें और ज्यादा काम करने के लिए बाध्य करना होगा।

कपिल के शो में नजर आएंगी एवरेस्ट विजेता नुंग्शी-ताशी

जागरण संवाददाता, देहरादून

- 'भारत का गौरव महिला शक्ति' पर आधारित है कॉमेडी शो का एपिसोड
- विश्व की सात सबसे ऊंची चोटी चढ़ने के अनुभवों को देश के साथ करेंगी साझा

एवरेस्ट विजेता देहरादून की जुड़वां बहनें नुंग्शी-ताशी कपिल शर्मा के शो में नजर आएंगी। इसमें वह विश्व की सात सबसे ऊंची चोटी चढ़ने के अनुभवों को देश के साथ शेयर कर महिला शक्ति का संदेश देंगी। वहीं, नुंग्शी-ताशी के कपिल शर्मा शो में आने की खबर से दूनवासियों में भी खुशी की लहर है।

एडवेंचर की शौकीन जुड़वां बहने नुंग्शी और ताशी मलिक दुनिया की सात सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई कर चुकी हैं। इसके साथ ही नुंग्शी-ताशी महिला सशक्तीकरण विषय पर महिलाओं को जागरूक करने के लिए सक्रिय रहती हैं। उनके इन्हीं प्रयासों को देखते हुए भारत के मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने अपने शो में विशेष अतिथि के रूप में उन्हें बुलाया है। एवरेस्ट विजेता बहनों के पिता और नुंग्शी-ताशी फाउंडेशन के सदस्य कर्नल (अप्रा) वीएस मलिक ने बताया कि कपिल शर्मा के शो से नुंग्शी-ताशी को स्पेशल गेस्ट का आमंत्रण मिला है। उन्होंने बताया कि शो की थीम भारत का गौरव महिला शक्ति है। इसमें नुंग्शी-ताशी के साथ भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज, झूलन गोस्वामी और वेदा कृष्णामूर्ति भी नजर आएंगी। उन्होंने बताया कि जुड़वां बहनों के अनुभव

से रूबरू होने के बाद देशभर में साहसिक खेलों को भी बढ़ावा मिलने की आशा है। नुंग्शी-ताशी उत्तराखंड की पहली दो बहने हैं जो द कपिल शर्मा शो में दिखेंगी। यह उत्तराखंड के लिए एक गौरव का पल है। उन्होंने सभी देशवासियों से आज रात साढ़े नौ बजे द कपिल शर्मा शो देखने की अपील की है।

छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री पीजीआइ में भर्ती, हालत गंभीर

जासं, लखनऊ : उत्तर प्रदेश आए छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रवींद्र चौबे की तबीयत बिगड़ गई। पहले उन्हें गोमती नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां सेहत में सुधार न होने पर उन्हें एसजीपीजीआइ में भर्ती कराया गया है।

पीजीआइ के एमआइसीयू में भर्ती मंत्री का उपचार कॉर्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टरों ने शुरू कर दिया है। डॉक्टरों के अनुसार मंत्री की हालत नाजुक है। दिल का दौरा पड़ने के बाद वे शॉक में चले गए हैं। इसके साथ उन्हें अन्य भी परेशानियां हैं।

चुनाव-प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रवींद्र चौबे को दिल का दौरा पड़ना बताया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें हार्ट अटैक के साथ ही किडनी, लिवर में भी दिक्कत है। मंत्री की किडनी व लिवर सही से काम नहीं कर रहे हैं। साथ ही सांस लेने में भी उन्हें तकलीफ हो रही है। पीजीआइ के सीएमएस डॉ. अमित अग्रवाल ने कृषि मंत्री की हालत गंभीर बताई है। उन्होंने बताया कि उपचार जारी है पर अभी उनकी हालत गंभीर है।

दैनिक जागरण के सहयोगी मीडिया प्लेटफॉर्म विश्वास.न्यूज की पड़ताल में सामने आया सच

जागरण की पुरानी खबर से किया जा रहा भ्रमित

विश्वास.News
क्योंकि सच जानना आपका अधिकार है
www.vishvasnews.com

जेएनएन, नई दिल्ली: सोशल मीडिया और वाट्सएप पर दैनिक जागरण अखबार की एक कटिंग वायरल हो रही है। कटिंग में लिखा है कि मोदी से पहले वाराणसी पहुंची दो ट्रक करेंसी। विश्वास न्यूज की पड़ताल में यह खबर दो साल से भी ज्यादा पुरानी निकली। लोकसभा चुनाव के वक्त इस पुरानी खबर के वायरल होने से लोगों में भ्रम फैल रहा है।

पड़ताल : विश्वास न्यूज की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रही कटिंग को ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। खबर का इंट्रो था: नकदी संकट से जूझ रहे पूर्वांचल के सभी जिलों के लिए यह बड़ी खबर है। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को करेंसी की भारी भरकम खेप वाराणसी पहुंचा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र में 22 दिसंबर को आगमन से पहले भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दो ट्रकों से लाई गई इस करेंसी से वाराणसी और आसपास के सभी जिलों में नकदी संकट समाप्त हो जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। खबर पढ़कर पता चला कि यह नोटबंदी के दौरान की कटिंग है। इसके बाद टीम ने गूगल में 'मोदी से पहले वाराणसी पहुंची दो ट्रक करेंसी' को सर्च किया तो jagran.com पर प्रकाशित एक खबर का लिंक मिला। इसे 18 दिसंबर 2016 को अपलोड किया गया था। इस खबर की हेडिंग अखबार की हेडिंग जैसी ही थी। पूरी खबर को पढ़ने के बाद पता चला कि वायरल कटिंग का कंटेंट और जागरण डॉट कॉम पर प्रकाशित खबर का कंटेंट एक ही है। अब यह जानना था कि क्या वाकई पीएम मोदी 22 दिसंबर 2016 को वाराणसी गए थे। इसके लिए टीम ने InVID टूल का प्रयोग किया। InVID के Twitter Search ऑप्शन में जाकर टीम ने @narendramodi टाइप करके 22 दिसंबर 2016 की डेट सेट करके पीएम के पुराने Tweet सर्च किए। यहां मोदी के वाराणसी दौरे के कई ट्वीट मिले। अंत में टीम ने पुरानी कटिंग को वायरल करने वाले Sagir Siddique की फेसबुक प्रोफाइल को स्कैन किया। इसके लिए टीम ने Stalkscan टूल का यूज किया तो पता चला कि यह शख्स समाजवादी पार्टी का समर्थक है।

क्या है वायरल पोस्ट में

'हम तो अखिलेश यादव के साथ हैं... और आप' नाम के फेसबुक ग्रुप पर Sagir Siddique नाम के फेसबुक यूजर ने अखबार की कटिंग को वायरल किया है। इसे 25 अप्रैल को अपलोड किया गया था।

झूठी खबर और अफवाहों की हकीकत जानने के लिए वाट्सएप करें:
9205 270 293

खुद की राइफल से एसएसबी जवान ने गोली मार कर जान दी

संवाद सूत्र, सिकंदरा (जमुई)

सिकंदरा थाना क्षेत्र के फुलवरिया कोड़ासी एसएसबी कैंप में शनिवार दोपहर एसएसबी के एक जवान वैभव कुमार सिंह ने खुद के राइफल से गोली मारकर खुदकशी कर ली। वैभव मुजफ्फरपुर 32वीं चार्ली बटालियन का जवान था। वह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में बहुनचारा लालगंज का रहने वाला था।

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यरत बटालियन को चुनावी ड्यूटी में यहां लगाया गया था। तबसे यह बटालियन फुलवरिया कोड़ासी कैंप में पदस्थापित है। दोपहर 12 बजे के करीब भोजन के लिए सभी जवानों को बुलाया गया, लेकिन वैभव मेस में जाकर भोजन नहीं कर वापस अपने बैरक में लौट आया। वहीं उसने अपना इंसास राइफल निकालकर ठुड्डी के नीचे राइफल को सटाकर गोली मारकर खुदकशी कर ली। गोली की आवाज सुनकर अन्य जवान जब बैरक की ओर दौड़े तो देखा कि जवान मरा पड़ा है। उसका राइफल भी वहीं गिरा पड़ा है। दूसरे जवानों ने इसकी सूचना अपने कमांडर को दी। वैभव ने 2013 में एसएसबी में नौकरी पाई थी। एक वर्ष पूर्व शादी हुई थी।

बाद में एसपी जे रेड्डी ने कैंप पहुंचकर घटनाक्रम की जानकारी ली। वहीं पुलिस निरीक्षक जयशंकर मिश्रा, थानाध्यक्ष राजबर्द्धन कुमार को प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत आवश्यक सुझाव दिया। पुलिस ने प्रक्रिया के तहत शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल जमुई भेज दिया। हालांकि खुदकशी के कारण का पता नहीं चल सका है।

आत्महत्या के कारणों की पड़ताल की जा रही है। जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद शव को पैतृक गांव भेजा जाएगा।

– जे रड्डी, एसपी, जमुई

हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में निजी बस खाई में गिरी, 10 लोगों की मौत

संवाद सहयोगी, डलहौजी

- चंबा-पठानकोट एनएच पर पंजपूला में हुआ हादसा, 28 घायल
- गंभीर रूप से घायल चार को मेडिकल कॉलेज टांडा व एक को चंबा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है
- पठानकोट से डलहौजी की ओर आ रही थी बस

हिमाचल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी के पास पंजपूला में निजी बस के 200 फीट खाई में गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। जबकि 28 लोग घायल हो गए। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। निजी कंपनी एटलस की बस पठानकोट से डलहौजी से आ रही थी कि 17 किलोमीटर पहले पंजपूला में यह हादसा पेश आ गया। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, डलहौजी पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

चंबा-पठानकोट राष्ट्रीय मार्ग पर शनिवार शाम हुए हादसे के बाद इलाके में चीखपुकार मच गई। आसपास के गांवों ने तुरंत राहत कार्य शुरू करते हुए पुलिस को सूचित किया। बताया जाता है कि बस में 35 से 40 लोग सवार थे। फिलहाल अभी दो मृतकों की पहचान हुई है। मृतकों में कीर्ति शर्मा उम्र 26 साल पत्नी पंकज शर्मा निवासी नूरपुर और मनीष शर्मा पुत्र देसराज निवासी नूरपुर के तौर पर हुई है जबकि अन्य मृतकों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। 16 घायलों को सिविल अस्पताल डलहौजी, चार घायलों को आशीर्वाद अस्पताल बनीखेत भेजा गया है। जबकि गंभीर रूप से घायल चार लोगों को मेडिकल कॉलेज टांडा व एक को चंबा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पठानकोट से डलहौजी की ओर आ रही निजी बस पंजपूला के पास अचानक अनियंत्रित होकर मार्ग से करीब दो सौ फीट गहरे नाले में जा गिरी। हादसे में बस में सवार सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन घायलों ने डलहौजी और बनीखेत के अस्पतालों में दम तोड़ा।

डीएसपी डलहौजी की अगुआई में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों के साथ राहत व बचाव कार्य शुरू किए व घायलों को नाले से बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया।

घायलों में कई की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिससे दुर्घटना में मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। एसपी चंबा डॉ. मोनिका ने हादसे में दस लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में घायल कई लोगों की हालत काफी नाजुक है।

चुनाव में तोते की तरह इस्तेमाल की जा रही सीबीआइ : मायावती

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- सरकारी चीनी मिलों की बिक्री मामले में मायावती ने दी सफाई
- कहा, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं, यह तो कैबिनेट का फैसला था

बसपा अध्यक्ष मायावती ने शनिवार को कहा कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन की सफलता और अपनी हार से बौखलायी भाजपा सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय जैसी जांच एजेंसियों का खुलकर दुरुपयोग कर रही है जो कि अब तक किसी और सत्ताधारी दल ने नहीं किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उप्र की सरकारी चीनी मिलों की बिक्री के मामले में उसने चुनाव के दौरान सीबीआइ का एक बार फिर तोते की तरह इस्तेमाल किया है। सफाई दी कि बसपा शासनकाल में हुई चीनी मिलों की बिक्री में बतौर मुख्यमंत्री उनकी न तो कोई भूमिका थी, न ही उन्होंने कोई निर्णय किया। यह तो कैबिनेट का फैसला था।

गौरतलब है कि बसपा शासनकाल में 21 सरकारी चीनी मिलों को औने-पौने बेचने के मामले की जांच कर रही सीबीआइ ने इस मामले में सात नामजद आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बसपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया से मुखातिब मायावती ने कहा कि चीनी मिलों की बिक्री की कार्यवाही स्थापित नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित विभाग द्वारा की गई थी। चीनी मिलों की बिक्री के संबंध में ऑडिट रिपोर्ट और लोकायुक्त की रिपोर्ट में भी मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की गई है। कहा कि यदि कहीं कोई कमी है तो उसकी जांच हो सकती है लेकिन, चुनाव के समय ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है कि जैसे इस मामले में मेरी पूरी भूमिका थी। मायावती ने कहा कि मीडिया के जरिये पता चला है कि चीनी मिलों की बिक्री मामले को सीबीआइ राजनीतिक रंग दे रही है। इतने पुराने मामले में चुनाव के दौरान सीबीआइ द्वारा केस दर्ज किया जाना इसका संकेत है।